ओडिशा...(**समय की घंटी**)... हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया है - हम लोगों की जो घेरी है, उसको वे कैसे डिमोलिश करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

धन्यवाद। माननीय डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी।

Demand to shift Health from State List to the Concurrent list of the Constitution

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री दोनों का आभार प्रकट करना चाहूंगा। इस देश में महिलाओं और बच्चों में खून की कमी के लिए उन्होंने 2018 में एनीमिया मुक्त अभियान चलाया। लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, वे बहुत encouraging नहीं हैं। वर्ष 2015-16 में छह महीने से छह साल के बच्चों में 58.6 प्रतिशत खून की कमी होती थी, जो आज 67.1 प्रतिशत है। गर्भवती महिलाओं में 50.5 प्रतिशत खून की कमी होती थी, आज वह 52.2 प्रतिशत है। किशोर बच्चों में 29.2 प्रतिशत खून की कमी होती थी, आज 31.1 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: झा साहब, आप बैठकर बात न करें। प्लीज़।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: किशोर बालिकाओं में 54.1 प्रतिशत खून की कमी होती थी, आज 59.1 प्रतिशत खून की कमी बालिकाओं में है। बहुत से ऐसे राज्य हैं, जैसे बिहार, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और जम्मू-कश्मीर राज्य हैं, जहां पर यह कमी बहुत अधिक मात्रा में है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

सर, मैं केरल का उदाहरण दूंगा कि शुरुआती दौर में इन्होंने खून की कमी पर बहुत अच्छा नियंत्रण किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले पांच सालों में केरल में भी खून की कमी 35 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई। शैशवकाल में यह 14 परसेंट से बढ़कर 27 परसेंट हो गई और गर्भवती महिलाओं में 22 परसेंट से बढ़कर 31 परसेंट हो गई। ...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, यह विषय मैं इसलिए लेकर आया हूं कि भारत सरकार के, माननीय प्रधान मंत्री जी के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सारे प्रयासों के बावजूद आज भी खून की कमी बढ़ती जा रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं प्रशंसा करूंगा कि इमरजेंसी ने बहुत सारे

काले इतिहास रचे हैं, लेकिन अनजाने में एक अच्छा काम हुआ। शिक्षा को राज्य सरकार के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में लाने का काम किया गया। मैं इस सदन से, इस सरकार से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए।

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

International cruise line in the country

*91. SHRI A.D. SINGH: Will the Minister of PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, at present, no international cruise line is touching the Indianshores;
(b) if so, the reasons therefor;
(c) whether Government intends to give incentives to attract international cruise lines; and
(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During 2022-23, 60 port calls and during 2023-24 (upto 31.10.2023), 29 port calls were made at various Indian Ports viz. Mumbai, Mormugao, New Mangalore, Cochin, Chennai and Tuticorin by international cruise liners.

(c) and (d) To attract International Cruise lines, several incentives have been given, as below.

(i) For berthing, cruise vessel is given priority over cargo vessel.
(ii) Rationalised cruise tariff has been introduced.